



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266067
CG-DL-E-11092025-266067

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3966]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2025/भाद्र 18, 1947

No. 3966]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2025/BHADRA 18, 1947

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)
(मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025

का.आ. 4081. (अ) —पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सहायिकी, प्रसुविधा और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सरकार कहा गया है) में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मंत्रालय कहा गया है) के प्रशासनिक दायरे के अधीन प्रमुख उर्वरक कंपनियां (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अभिकरण कहा गया है) नमो ड्रोन दीदी योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त योजना कहा गया है) का संचालन कर रही हैं:

और, महिला स्वयं-सहायता समूहों के बैंक हस्ताक्षरकर्ता और उनके क्लस्टर स्तरीय संघों (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा प्राप्तकर्ता कहा गया है) को उक्त योजना और उसके संबंध में जारी किए गए अनुदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन अस्सी प्रतिशत तक अधिकतम आठ लाख रुपये (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त फायदा कहा गया है) की वित्तीय सहायता दी जाती है:

और, उक्त योजना के लिए व्यय भारत की संचित निधि से उपगत किया जाता है:

और, उक्त मंत्रालय यह चाहता है कि उक्त सरकार उक्त प्रसुविधा की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में प्रसुविधा प्राप्तकर्ता की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से, यह अपेक्षा करती है कि ऐसे प्रसुविधा प्राप्तकर्ता को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या उनके पास आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कोई आधार संख्या नहीं मिली है, उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा:

अतः, भारत सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 18) [जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है] की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्—

1. (1) उक्त योजना के अधीन उक्त प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण कराना होगा अथवा आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उस मामले में नामांकन के लिए आवेदन करना होगा:

परंतु यदि वह व्यक्ति बालक है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रसुविधा प्राप्तकर्ताओं का नामांकन किया जाए जो अभी तक नामांकित नहीं हैं, या उनके आधार विवरण को उचित उपायों के माध्यम से अपडेट किया जाए, जिसमें रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करना शामिल है:

परंतु जब तक ऐसे प्रसुविधा प्राप्तकर्ताओं को आधार नंबर आवंटित नहीं किया जाता है, वह निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी पहचान स्थापित कर सकता है जिनके लिए वह पात्र है और जो प्रस्तुति के समय विधिमान्य हैं, या, ऐसे मामले में जहां ऐसे पहचान के लिए उक्त मंत्रालय द्वारा सॉफ्टवेयर प्रदान या अनुमोदित किया गया है, जो इसके तैयार कर्ता या रख-रखाव करने वाले प्राधिकरण के डेटाबेस से ऐसे दस्तावेजों की सत्यापन सूचना, ऐसा करने की सहमति देकर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हासिल करने की सुविधा देता है, अर्थात्:-

उन प्रसुविधा प्राप्तकर्ताओं जिनकी उम्र अठारह वर्ष या उससे अधिक है और जिन्हें आधार नंबर नहीं सौंपा गया है के लिए:-

(क) प्रसुविधा प्राप्तकर्ता द्वारा नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेने पर नामांकन केंद्र में ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई ईआईडी वाली पावती

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों जिसमें प्रसुविधा प्राप्तकर्ता की तस्वीर हो, में से कोई एक अर्थात्:-

(i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो राजपत्रित अधिकारी है या राज्य सरकार के राजस्व अधिकारी है जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं है, द्वारा जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जारी किया गया हो;

(iv) किसी सरकारी इकाई या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम द्वारा एक सेवानिवृत्त या सेवारत सरकारी सेवक या उनके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र या अंकपत्र;

(vii) एक सरकारी इकाई या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम द्वारा एक सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;

(ix) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस:

(xi) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र; या

(xi) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक संरक्षक, दत्तक ग्रहण आदेश या वैधानिक संरक्षकता के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज हैं, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या

(xii) कोई अन्य दस्तावेज जिसे उक्त मंत्रालय निर्दिष्ट करे:

(4) उक्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषय-वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना के संबंध में जांच करेगा,—

क. माय आधार पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर ईआईडी जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करें, ताकि यह पुष्टि हो सके कि ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; तथा

ख. अन्य दस्तावेजों के संबंध में तथा इस प्रयोजन के लिए किसी सरकारी संस्था या प्राधिकरण की सहायता ले सकता है तथा प्रस्तुत जानकारी को उसके साथ साझा कर सकता है, जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।

7. प्रसुविधा प्राप्तकर्ताओं को उक्त लाभ आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मंत्रालय उक्त योजना के अधीन आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में प्रसुविधा प्राप्तकर्ताओं को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

8. जहां किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से लाभार्थी के आधार संख्या का प्रमाणीकरण किसी भी कारण से विफल हो जाता है जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:—

क. यदि प्रमाणीकरण का कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, पेश किया जाएगा;

ख. ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के बायोमेट्रिक-आधारित या ओटीपी-आधारित तरीके संभव नहीं हैं, उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के बाद, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकता है:

(iii) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात् आधार संख्या धारक को उसके आधार संख्या के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात् यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके

एक्सेस करने योग्य), आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद।

(iv) आधार पेपरलेस ऑफ़लाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके सुलभ है), इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद, यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार।

9. ऊपर दी गई किसी भी बात के होते हुए भी—

क. उक्त योजना के अधीन किसी बालक को प्रसुविधा देने से इनकार नहीं किया जाएगा—

i. प्रमाणीकरण करवाकर अपनी पहचान स्थापित करने में असफल रहने अथवा आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में; अथवा

ii. नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में, जहां उसे आधार संख्या नहीं दी गई है; तथा

ख. उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित करके और उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके पैरा 1 के खंड (3) के परंतुक में निर्दिष्ट तरीके से दिया जाएगा; तथा

ग. जहां खंड (ख) के अधीन प्रसुविधा दी जाती है, वहां उसके संबंध में रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा और लेखा-परीक्षा की जाएगी।

10. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक प्रसुविधा प्राप्तकर्ता उक्त योजना के अधीन मिलने वाले प्रसुविधा से वंचित न रहें, मंत्रालय प्रत्यक्ष प्रसुविधा अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी (<https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

11. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभाव में आएगी।

[फा. सं. 13-23/2024-एम एंड टी (आई एंड पी)]

एस. रुक्मणी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

(Mechanization and Technology Division)

NOTIFICATION

New Delhi, 11th August, 2025

S.O. 4081(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas Lead fertilizer Companies (hereinafter referred to as the said agency) under the administrative purview of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, (hereinafter referred to as the said Ministry) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering Namo Drone Didi Yojana (hereinafter referred to as the said scheme):

And whereas financial assistance up to eighty percent to a maximum of rupees eight lakhs (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the Bank signatory of Women Self help Groups and their Cluster Level Federations (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof:

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India:

And whereas the said Ministry is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act 18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
- (2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

- (3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Ministry shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Ministry for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For beneficiaries aged eighteen years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and
- (b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
 - (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
 - (ii) Ration card;
 - (iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
 - (iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (v) Indian passport;

- (vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
- (vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
- (viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;
- (ix) Driving licence issued in India;
- (x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
- (xi) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (xii) Any other document as the said Ministry may specify:

(4) An officer designated by the said Ministry in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

- (a) the status of the enrolment request by submitting the EID on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
- (b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.
3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
 - (a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following namely:

- (i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.
- (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. Not with standing anything contained hereinabove,—

(a) benefit under the said scheme shall not be denied to a child—

- (i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or
- (ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and

(b) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and

(c) Where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry.

5. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged eighteen years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Ministry shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).

6. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

[File No. 13-23/2024-M and T (I and P)]

S. RUKMANI, Jt. Secy.